www.sanjanabharati.com

दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित

facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 आतंकवाद में डिजिटल तकनीकों का बढ़ता...

3 दीपक राय कान्हा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का...

4 केंद्र सरकार की रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन...

वर्ष: 9 | अंक: 261 | दिल्ली, मंगलवार, 15 जुलाई 2025 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

अब सभी विमानों में इंजन फ्यूल स्विच की जांच अनिवार्य

नई दिल्ली (एजेन्सी)। भारत के विमानन नियामक ने सोमवार को देश की सभी एयरलाइनों को 21 जुलाई तक 787, 747 और 737 मॉडल सहित बोइंग विमानों के ईंधन स्विचों की जांच करने का आदेश दिया है, ताकि उनके लॉकिंग तंत्र में खराबी की जांच की जा सके। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा यह कदम 12 जून को एयर इंडिया विमान दुर्घटना पर 15 पृष्ठों की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि विमान के इंजन को ईंधन की आपूर्ति करने वाले स्विच उड़ान भरने के एक सेकंड के भीतर बंद कर दिए गए थे जो इस त्रासदी के पीछे प्रमुख कारणों में से एक था। एसएआईबी के एक विशेष उड़ान योग्यता सूचना बुलेटिन में इसका उल्लेख किया गया था, हालांकि इसमें कोई ऐसा संकेत नहीं था, जिससे यह मुद्दा सुरक्षा संबंधी चिंता का विषय लगे। डीजीसीए ने सोमवार को कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू परिचालकों ने एफएए के एसएआईबी के अनुसार अपने विमान बेड़े का निरीक्षण शुरू कर दिया है।

मेरठ में स्कूल बस की टक्कर से तीन कांवड़िए घायल

मेरठ (एजेन्सी)। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले मेंकांवड़ यात्रा के दौरान उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक स्कूल बस ने जल लेकर जा रहे तीन कांवड़ियों को टक्कर मार दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में तीनों श्रद्धालु घायल हो गए, जिसके बाद नाराज कांवड़ियों ने बस में तोड़फोड़ की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह मामले को शांत कराया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह घटना जिले के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेगमपुल चौकी के पास दिल्ली मार्ग पर हुई। गाजियाबाद निवासी संदीप, बॉबी और अभिषेक हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे थे, तभी कैंट अस्पताल के समीप पीछे से आई स्कूल बस कांवड़ियों से मामूली रूप से टकरा गई। टक्कर लगते ही तीनों कांवड़िए घायल हो गए। इस घटना से आक्रोशित अन्य कांवड़ियों ने बस को घेर लिया और उसके शीशे तोड़ डाले। उन्होंने बस चालक के साथ मारपीट भी की, जो घबराकर वाहन छोड़कर भाग निकला। इस घटना के चलते कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।

आंध्र प्रदेश के तिरुपति में ट्रेन के खाली डिब्बे में आग लगी

आंध्र प्रदेश (एजेन्सी)। आंध्र प्रदेश के तिरुपति रेलवे स्टेशन पर रखरखाव के लिए खड़ी एक ट्रेन के एक खाली डिब्बे में आग लग गई, जिसे तुरंत बुझा दिया गया। रेलवे के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आग अपराह्न करीब दो बजे लगी और इसमें किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है। अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, अपराह्न करीब दो बजे केवल एक डिब्बे में आग लगी। इसे बहुत जल्दी काबू में कर लिया गया। दमकल विभाग ने आकर तुरंत आग पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने कहा कि जांच के बाद आग के कारणों का पता लग पाएगा। इस बीच, दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) जोन की एक विज्ञप्ति में ट्रेन की पहचान हिसार-तिरुपति स्पेशल (ट्रेन संख्या 04717) के रूप में की गई है।

उत्तराखंड के सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की

पीआईबी/नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिले। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया-उत्तराखंड के मुख्यमंत्री @pushkardhami ने प्रधानमंत्री @narendramodi से मुलाकात की।

कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी-रेखा गुप्ता

नई दिल्ली (एजेन्सी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ दिन पहले शाहदरा में यात्रा मार्ग पर कांच के टुकड़े बिखरे पाए गए थे। एक कार्यक्रम में बोलते हुए, गुप्ता ने यात्रा में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि उनकी सरकार कांवड़ियों को सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगभग 400 मीटर तक कांच के टुकड़े बिखरे हुए पाए गए। किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कांवड़ यात्रा में कोई सुरक्षा बाधा या रुकावट पैदा की जाती है, तो संबंधित व्यक्ति को सरकार को जवाब देना होगा। एक कार्यक्रम से इतर उन्होंने कहा कि सरकार शिवभक्तों के लिए पूरी तरह सुरक्षित और आरामदायक कांवड़ यात्रा सुनिश्चित करेगी। हम पूरी सुविधाएँ देंगे और कांवड़ियों का स्वागत करेंगे। पुलिस ने रविवार को बताया कि दिल्ली के शाहदरा में कांवड़ यात्रा मार्ग पर एक ई-रिक्शा चालक को हिरासत में लिया गया, क्योंकि उसके वाहन पर ले जाए जा रहे शीशे टूटकर बिखर गए।

हमारी सरकार का लक्ष्य दिल्ली को मेडिकल हब बनाना है: सीएम

दिल्ली सरकार 'स्वस्थ दिल्ली, सशक्त दिल्ली' नीति के लिए लगातार कार्यरत

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि उनकी सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली, देश का ऐसा मेडिकल हब बने, जहां कोई भी मरीज निराश न लौटे और यहां देश-विदेश से भी लोग इलाज कराने आएं। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार सात अधूरी अस्पताल परियोजनाओं को सुपर स्पेशलिटी आईसीयू केंद्रों में बदल रही है, जहां विभिन्न गंभीर बीमारियों के लिए विशेष इलाज की सुविधा होगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह जानकारी आज उत्तरी दिल्ली स्थित मॉडल टाउन क्षेत्र में नवनिर्मित यथार्थ मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन पर दी। यह अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भी सेवाएं देगा, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं निशुल्क मिल सकेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार ही नहीं कर रही, बल्कि उसे सुलभ, पारदर्शी और जन-संवेदनशील भी बना रही है। हमारी सरकार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर राजधानी को एक मॉडल हेल्थकेयर सिस्टम की ओर ले जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि दिल्लीवासियों को तो बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, साथ ही देश की राजधानी को हम ऐसे मेडिकल हब में बदलें, जहां देश-विदेश से लोग इलाज कराने आएं और उन्हें दिल्ली के अस्पताल, डॉक्टरों और स्वास्थ्य प्रणाली पर पूर्ण विश्वास हो।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इसी आवश्यकता को देखते हुए दिल्ली सरकार सात अधूरी अस्पताल परियोजनाओं को सुपर स्पेशलिटी आईसीयू केंद्रों में बदल रही है, जहां विभिन्न गंभीर बीमारियों के लिए विशेष इलाज की सुविधा होगी। हर अस्पताल को अलग बीमारी के इलाज के लिए समर्पित किया जाएगा, जैसे कैंसर, ट्रांसप्लांट या डिलीवरी के जटिल मामले। इसके साथ ही आईसीयू बेड्स की कमी को भी दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का सपना है कि कोई भी नागरिक इलाज से वंचित न रहे। न आर्थिक कारणों से, न संसाधनों की कमी से।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नवनिर्मित अस्पताल अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीकों और बहुविशेषज्ञ सेवाओं से सुसज्जित है, जो दिल्ली सरकार की 'स्वस्थ दिल्ली, सशक्त दिल्ली' नीति को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भी सेवाएं देगा, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं निशुल्क मिल सकेंगी।

सीएम नायब सिंह सैनी ने स्वामी कल्याणदेव महाराज जी की 21वीं पुण्यतिथि पर किया नमन

समाज और देश की प्रगति के लिए प्रत्येक व्यक्ति निरंतर सेवा भाव से करें कार्य-सीएम

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) में स्थित शुकदेव आश्रम में स्वामी कल्याणदेव महाराज जी की 21वीं पुण्यतिथि पर उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वामी कल्याण देव जी महाराज की प्रतिमा का भी अनावरण किया।

श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज हम माँ गंगा के पावन तट पर स्थित महान महर्षि शुकदेव की धरती पर एकत्रित हुए हैं। भागवत पीठ श्री शुकदेव आश्रम विशेष स्थान है। यह आश्रम न केवल एक आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि शिक्षा, सेवा और संस्कृति का भी प्रतीक है। स्वामी जी की प्रतिमा नई पीढ़ियों को

स्वामी जी के कार्यों, सिद्धांतों और आदर्शों की हमेशा याद दिलाती रहेगी।

उन्होंने कहा कि स्वामी ओमानन्द जी महाराज इस आश्रम की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और शुकदेव जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए समाज सेवा के कार्यों को सेवा भाव से कर रहे हैं। स्वामी जी के मार्गदर्शन में इस आश्रम का शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि इस धरती पर हजारों साल पहले महर्षि शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित को भागवत कथा सुनाकर मोक्ष का मार्ग दिखाया था।

इस महान तीर्थ के उद्धार में संत कल्याणदेव महाराज ने अपना पूरा जीवन लगाया था। स्वामी कल्याणदेव जी महाराज का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके विचार और कार्य असाधारण थे। उन्होंने कम उम्र में ही सांसारिक मोह माया का त्याग कर आध्यात्मिक पथ अपनाया। यह पावन भूमि इसी महान संत, शिक्षाविद और समाज सुधारक की तपोभूमि है। वे केवल एक संत नहीं थे, वे अपने आप में एक संस्था थे, जहां से मानवता और समाज सेवा की धारा निरंतर बहती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में दोषी की जेल की सजा कम की

नई दिल्ली (एजेन्सी)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बलात्कार के मामले में सजायाफ्ता एक व्यक्ति की जेल की सजा 30 साल से घटाकर 20 वर्ष कर दी है। न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने 11 जुलाई को पारित आदेश में कहा, निचली अदालत ने याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2)(आई) और (एन) के तहत 30 साल की सजा सुनाते हुए दर्ज किया था कि उसका अपराध जघन्य प्रकृति का था और इसलिए उसे दी गई सजा उचित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता का अपराध अत्यंत गंभीर है। अदालत ने कहा कि यह रिकॉर्ड में आने के बाद कि दोषी जेल में सफाई सहायक के रूप में काम कर रहा था और उसका आचरण संतोषजनक था, उसकी सजा की अवधि में संशोधन किया गया।

भगवंत सिंह मान ने विधानसभा में 'पंजाब धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ अपराध रोकथाम विधेयक, 2025' पेश किया

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। प्रदेश में बेअदबी की घटनाओं को रोकने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 'पंजाब विधानसभा में धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ अपराध रोकथाम विधेयक, 2025' पेश किया।

सदन में विधेयक पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक भावनात्मक और संवेदनशील मुद्दा है जो हर पंजाबी से संबंधित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे के न केवल वर्तमान में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी गंभीर परिणाम हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस अक्षम्य अपराध के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करना समय की मांग है ताकि अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पंजाब महान गुरुओं, संतों-महापुरुषों और पीर-पैगंबरों की पवित्र भूमि है, जिन्होंने सभी को आपसी प्रेम और सहिष्णुता का मार्ग दिखाया। उन्होंने अफसोस जताया कि कुछ पंजाब विरोधी ताकतें 2016 से पवित्र ग्रंथों की बेअदबी जैसे पाप को अंजाम देकर प्रदेश के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं। भगवंत सिंह मान ने ऐसी घटनाओं के दोषियों के लिए नजीर बनने वाली सजा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने प्रमुख कानूनी विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा करके सख्त कानून तैयार किया है, जिसमें ऐसे घृणित अपराधों के लिए कठोर से कठोर सजा का प्रावधान किया गया है ताकि अपराधी अपने अक्षम्य अपराधों के गंभीर परिणामों से किसी भी बहाने बच न सकें। न्याय के प्रति अपनी सरकार के समर्पण को दोहराते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि इन अपमानजनक कृत्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हर व्यक्ति को अनुकरणीय सजा का सामना करना पड़ेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसे खतरनाक अपराधियों को उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराना राज्य सरकार का नैतिक कर्तव्य है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर कोई कानून या समाधान नहीं लाने के लिए विपक्ष की कड़ी आलोचना की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बरगाड़ी और बहबल कलां जैसी घटनाओं ने हर पंजाबी के मन को गहरी ठेस पहुंचाई है। उन्होंने आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे विधेयक पर चर्चा के लिए भी कांग्रेस नेताओं ने और समय मांगा है, जो इस मामले के प्रति उनकी गंभीरता की कमी को दर्शाता है। इस दौरान भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि जब मंगलवार को विधेयक पर चर्चा फिर से शुरू होगी, तब कांग्रेस नेता सरकार के साथ सहयोग के लिए तैयार होकर आएंगे ताकि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जा सके।

गन्नौर इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने की समीक्षा बैठक

निर्माण कार्यों में तेजी लाने और परियोजना को तय समयावधि में पूर्ण करने के दिए निर्देश

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को जिला सोनीपत के गन्नौर स्थित 'इंडिया इंटरनेशनल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट' का दौरा कर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने मंडी प्रशासन, निर्माण कंपनी व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और निर्माण कार्यों में तेजी लाने व परियोजना को तय समयावधि में पूर्ण करने के दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना न केवल हरियाणा के किसानों बल्कि देशभर के फल, सब्जी, फूल, मछली, पोल्ट्री व डेयरी उत्पादकों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच दिलाने का सशक्त माध्यम बनेगी। यह मार्केट राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर स्थित है और इसकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से बेहतर कनेक्टिविटी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 220 करोड़ रुपये की लागत से 544 एकड़ 2 कनाल भूमि अधिग्रहण कर इस परियोजना की शुरूआत की गई थी, जिसकी कुल लागत 2,595 करोड़ रुपये आंकी गई है। अब तक निर्माण कार्य का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा पूरा किया जा चुका है और 689 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस

अंतरराष्ट्रीय मंडी में कुल 50 लाख वर्ग फीट का कवर एरिया होगा, जिसकी क्षमता 20 लाख टन प्रतिवर्ष होगी। इसमें 14,907 कारों तथा 3,305 ट्रकों/ट्रॉलियों की पार्किंग की सुविधा होगी। साथ ही 17 मार्केटिंग एवं ट्रेडिंग शेड और 13 अन्य आधुनिक इमारतें भी तैयार की जाएंगी। उन्होंने निर्देश दिए कि संचालन समिति कार्य में तेजी लाए और किसानों को जल्द से जल्द इस परियोजना से लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने मंडी में सौर ऊर्जा को लेकर आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने अवगत कराया कि परियोजना के अंतिम चरण में 28 मेगावाट सोलर ऊर्जा की व्यवस्था की गई है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षमता को और अधिक बढ़ाया जाए ताकि मंडी ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने रेनीवेल (पेयजल आपूर्ति) कार्य को शीघ्र आरंभ करने के निर्देश दिए ताकि मंडी में समय पर जल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने व मंडी से निकलने वाले वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कर दोबारा उपयोग किए जाने के भी निर्देश दिए।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस मंडी को विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त एक आदर्श बागवानी केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है, जो किसान हित में कार्य करे और कृषि आधारित निर्यात को बढ़ावा दे। निर्माण कंपनी को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वे कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता दोनों सुनिश्चित करें। यह बागवानी मंडी न केवल आधुनिक विपणन प्रणाली का प्रतीक बनेगी, बल्कि किसानों की आय को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।

इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, विधायक कृष्णा गहलावत, देवेंद्र कादियान, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र बढ़खालसा, नगर निगम मेयर राजीव जैन, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल, हरियाणा अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी कॉरपोरेशन के मुख्य प्रशासक मुकुल कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

संवेदनशीलता के साथ जन सेवा ही हमारा मूलमंत्र-भजनलाल शर्मा

एसबी संवाददाता

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ सेवा को अपना मूल मंत्र मानते हुए आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रही है। हमने प्रदेशभर में जनसुनवाई का ऐसा तंत्र सुविकसित किया है जो परिवादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के साथ ही जरूरतमंद को त्वरित सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने में बेहद कारगर साबित हो रहा है।

श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जनसुनवाई कर रहे

थे। उन्होंने आमजन की परिवेदनाओं को आत्मीयता के साथ सुना तथा अधिकारियों को उनके संतोषपूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी सुराज के संकल्पों को साकार करने की दिशा में आमजन को बुनियादी सुविधाएं नियमित और निर्बाध रूप से उपलब्ध कराए। जनकल्याण ही राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, कृषि, गृह, राजस्व, सिंचाई, परिवहन, पशुपालन, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, मनरेगा, ऊर्जा सहित विभिन्न विभागों की आमजन से जुड़ी परिवेदनाओं को सुना और उनका मौके पर ही निस्तारण किया।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे।

सम्पादकीय

देश और समाज के लिए तन, मन, धन समर्पित करने की मिसाल हैं सी. सदानंदन मास्टर

पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मामले में विशेष लोक अभियोजक रहे उज्ज्वल निकम, केरल से भारतीय जनता पार्टी के नेता सी सदानंदन मास्टर और इतिहासकार मीनाक्षी जैन को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। इन चार नामों में से आपके लिए सी. सदानंदन मास्टर का नाम भले जाना-पहचाना नहीं हो लेकिन उनके सामाजिक कार्य उनकी पहचान हैं। साथ ही उनका जीवन अन्याय के आगे नहीं झुकने की भावना का प्रतीक भी है। वामपंथी हिंसा और धमकी के आगे नहीं झुक कर राष्ट्र के विकास के प्रति अपने जज्बे को बरकरार रखने वाले सी. सदानंदन मास्टर पूरे देश के लिए बड़ी प्रेरणा हैं। हम आपको बता दें कि केरल के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में जिन व्यक्तियों ने जनता के बीच संगठन, चेतना और संघर्ष की लौ जगाई, उनमें सी. सदानंदन मास्टर का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। वे केवल एक शिक्षक नहीं हैं, बल्कि जीवनपर्यंत एक ऐसे संगठक, विचारक और मार्गदर्शक रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठनों के माध्यम से केरल में राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूती दी। उनका जीवन संघर्ष, तपस्या और आदर्शों के लिए समर्पित रहा है, और आज भी वे केरल के राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। सी. सदानंदन मास्टर का जन्म केरल के कन्नूर जिले के एक साधारण परिवार में हुआ। बाल्यकाल से ही वे अत्यंत संयमी, मेहनती और अनुशासनप्रिय थे। शिक्षा के प्रति उनकी रुचि प्रारंभ से ही गहरी थी। उन्होंने शिक्षक के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की और बहुत जल्द गांव-समाज में एक आदर्श गुरु के रूप में प्रसिद्ध हो गए। सदानंदन मास्टर का जीवन तब मोड़ लेता है, जब वे युवावस्था में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आते हैं। संघ के 'एकात्म मानववाद', सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारतीयता के विचार ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। शिक्षक के दायित्व के साथ-साथ वे धीरे-धीरे संगठनात्मक कार्यों में भी सक्रिय हो गए। उनका घर और स्कूल ही संघ की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। वे विद्यालयों में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा को प्राथमिकता देते थे। हम आपको बता दें कि केरल के कन्नूर और आसपास के क्षेत्र वामपंथी राजनीतिक हिंसा के लिए कुख्यात रहे हैं। 1994 में सी. सदानंदन मास्टर पर एक क्रूर और अमानवीय हमला हुआ। मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े हिंसक कार्यकर्ताओं ने उनके दोनों पैर काट डाले थे। यह हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विचारधारा, शिक्षा और संगठन के प्रति समर्पण पर हमला था। लेकिन सदानंदन मास्टर ने इस हिंसा के आगे कभी घुटने नहीं टेके। उन्होंने इस घटना को अपने जीवन का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत माना। उन्होंने स्वयं कहा था कि मेरे पैर काट दिए, लेकिन मेरे विचार और हौसले कोई नहीं काट सकता। हम आपको बता दें कि इस घटना के बाद वे पूरे केरल और देशभर में "साहस और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक" के रूप में पहचाने जाने लगे। वे पूरी ताकत के साथ संगठन के कार्यों में जुट गए थे। उन्होंने शारीरिक अपंगता को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने हजारों युवाओं को राष्ट्र के प्रति समर्पण, सेवा और संगठन के मार्ग पर चलाया। वामपंथी हिंसा से त्रस्त केरल के लोगों में उनके प्रति विशेष सम्मान और श्रद्धा पैदा हुई। वे अनेक युवाओं के लिए जीते-जागते आदर्श बन गए कि किस तरह विचार और ध्येय के लिए तन, मन, जीवन सब कुछ समर्पित किया जाता है। हम आपको बता दें कि सदानंदन मास्टर ने संघ और उससे जुड़े संगठनों में संगठनकर्ता, प्रेरक वक्ता और मार्गदर्शक के रूप में वर्षों तक कार्य किया। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सेवा भारती, विद्या भारती और भाजपा में सक्रिय रहे हैं। वे सदैव युवाओं को प्रेरित करते रहे हैं कि शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए होनी चाहिए। उनकी वाणी में इतना प्रेरक तेज और सच्चाई होती है कि श्रोता स्वतः उनके विचारों से जुड़ जाते हैं। सदानंदन मास्टर सादगी, संयम और अनुशासन के प्रतीक हैं। उन्होंने कभी पद, प्रतिष्ठा या प्रचार नहीं चाहा। वे हमेशा संघ और समाज के अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता की तरह कार्यरत रहते हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व नारे या भाषणों से नहीं, बल्कि अपने आचरण और संघर्ष से पैदा होता है। आज केरल में जो हजारों, लाखों युवा राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ खड़े हैं, समाज सेवा और संगठन में लगे हैं, उसके पीछे सदानंदन मास्टर जैसे व्यक्तित्वों की दशकों की तपस्या और प्रेरणा है। वे एक जीवित उदाहरण बनकर यह साबित कर पाने में सफल रहे हैं कि हिंसा से विचार नहीं मारे जा सकते। बहरहाल, सी. सदानंदन मास्टर का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि विचार, साहस और सेवा के आदर्शों की जीवंत गाथा है। उनके दोनों पैर काटे गए, लेकिन उनके विचार केरल में हजारों लोगों के जरिए समाज निर्माण में लगे हैं। अब तो वह राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हो गये हैं और निश्चित ही देश को उनके विचारों और अनुभवों का लाभ मिलेगा। स्त्रोत: प्रभासाक्षी

जयंती

जमशेद जी जीजाभाई

जन्म: 15 जुलाई, 1783 ई.; मृत्यु: 14 अप्रैल, 1859) भारतीय-पारसी व्यापारी और परोपकारी थे, जो बाद में एक ब्रिटिश शूरवीर और बैरोनेट थे। उन्होंने चीन के साथ कपास और अफीम के व्यापार में सफलता पाई। वह अपने व्यवसाय से अत्यंत धनी बने दानवीर थे। जमशेद जी जीजाभाई का सबसे अधिक नाम उनकी दानशीलता के कारण है।

पुण्यतिथि

बानो जहाँगीर कोयाजी

जन्म: 7 सितम्बर, 1917; मृत्यु: 15 जुलाई, 2004) भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक थीं। बानो पारसी सम्पन्न परिवार में पली बढ़ी थीं। ये परिवार नियोजन की पक्षधर तथा विशेषज्ञ भी थीं। इन्होंने अपने कॅरियर की शुरूआत सन 1943 में 'स्त्री रोग तथा प्रसूति' में की। वहाँ अपनी प्रैक्टिस करने के बजाय डॉ. इडुल्जी कोयाली के साथ बतौर सामान्य डॉक्टर के रूप में कार्य किया। 14 मई 1944 में किंग एंडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल (ङएट) के चेयरमैन सरदार मुदलियार ने खुद बानो को आमंत्रित कर एक कुशल डॉक्टर पद सम्भालने का कार्य किया। बानो ने 1972 में ङएट में छोटा क्लीनिक वाडू में स्थापित कर, वहाँ प्रसूति तथा परिवार नियोजन कार्यक्रमों को ऊपर रखते हुए व्यवस्था भी की। इन्होंने पुणे में अस्पताल को अपने कार्य क्षेत्र का माध्यम बना करके अपना व्यापक योगदान इस दिशा में दिया कि महाराष्ट्र की ग्रामीण स्त्रियों तथा उनके परिवारों के जीवन में सुधार आये।

कल मिलेंगे

बॉयफ्रेंड-जन्मदिन मुबारक हो डार्लिंग
बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए मुझसे
गर्लफ्रेंड-बस अपना एटीएम नंबर और पासवर्ड बता दो और मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए
बॉयफ्रेंड का मोबाइल स्विच ऑफ.

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।
RNI No. : DELHIN/2016/70240
Phone No.: 9871221635
E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com
(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

मतदाता सूची में सुधार पर सुप्रीम सहमति सराहनीय

भारतीय लोकतंत्र की नींव निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी चुनावों पर टिकी होती है। इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने की दिशा में बिहार में चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया मतदाता सूची सुधार अभियान हाल ही में राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना। लेकिन जिस बात ने सबसे अधिक ध्यान खींचा, वह यह है कि इस पूरी कवायद के दौरान विपक्ष एक बार फिर एकजुट होकर इसका विरोध करता नजर आया, भले ही मामला राष्ट्रहित और लोकतंत्र की मजबूती से जुड़ा हो

-ललित गर्ग

बिहार में मतदाता सूची सुधार पर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी सिर्फ एक न्यायिक फैसला नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मूल्य को पुष्ट करने वाला ऐतिहासिक एवं प्रासंगिक निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा के लिए आधार, राशन और वोटर कार्ड को भी मान्यता देने का सुझाव देकर आम लोगों की मुश्किल हल करने की कोशिश की है। इससे प्रक्रिया आसान होगी और आशंकाओं को कम करने में मदद मिलेगी। बेशक, फर्जी नाम मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए लेकिन ऐसे अभियानों के दौरान आयोग का जोर ज्यादा से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से निकालने के बजाय, इस पर होना चाहिए कि एक भी नागरिक चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित न रह जाए। विपक्ष को चाहिए कि वह इस फैसले को राजनीतिक हार न माने, बल्कि इसे एक अवसर माने, जनविश्वास अर्जित करने का, लोकतंत्र में आस्था बढ़ाने का और सबसे जरूरी, राष्ट्रहित को राजनीति से ऊपर रखने का। मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य केवल बिहार ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ करना चाहिए।

भारतीय लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होता है। चुनाव आयोग यदि चुनाव कराने को तैयार है, और इसकी जुड़ी किन्हीं प्रक्रियाओं में कोई त्रुटि या खामी है तो उसका सुधार करना संविधान सम्मत है, तो फिर इस पर प्रश्नचिन्ह लगाने का अधिकार किसी भी राजनीतिक दल को नहीं होना चाहिए। लेकिन जो प्रश्न जनता के मानस को उद्वेलित करता है, वह यह है कि विपक्ष बार-बार चुनावी प्रक्रियाओं, राष्ट्रीय हितों या सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी एकमत होकर विरोध करता है, आखिर क्यों? बिहार में एसआईआर को लेकर जो याचिकाएं और बहसें सामने आईं, उनमें एक प्रमुख तर्क यह था कि समय उपयुक्त नहीं है, सरकार अस्थिर है, या सामाजिक समीकरण तैयार नहीं हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनता को प्रतिनिधित्व देने का अधिकार सर्वोपरि है। लेकिन त्रुटिपूर्ण या फर्जी मतदाता सूची से चुनाव कराना भी लोकतंत्र का अपमान है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि देर-सवेर नहीं, संवैधानिक कर्तव्य को समय पर निभाना जरूरी है।

अदालत ने एसआईआर पर कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन अपने इरादे की ओर इशारा तो कर ही दिया है। अदालत ने टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठाया, वह उचित प्रतीत होता है। बिहार में इसी साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इतनी विस्तृत कवायद के लिए शायद उतना वक्त न मिल पाए, जितना मिलना चाहिए। बिहार में एसआईआर को लेकर जो असमंजस है, उसकी एक वजह निश्चित ही टाइमिंग है। जिनके पास जरूरी डॉक्युमेंट नहीं हैं, वे इतनी जल्दी उनका इंतजाम नहीं कर पाएंगे। हालांकि आयोग ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का मौका दिए बिना मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। वैसे बिहार में चुनाव को देखते हुए ही फर्जी मतदाताओं की संख्या बढ़ी या तथाकथित राजनीतिक दलों ने इन फर्जी मतदाताओं को बढ़ाया है। ऐसे में इन फर्जी मतदाताओं पर कार्रवाई अपेक्षित है। यह मामला केवल बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहिए। दूसरे राज्यों में मतदाता सूचियों की समीक्षा किस तरह होगी, यह बिहार में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। ऐसे में स्वाभाविक ही नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार इस प्रक्रिया का कैसा स्वरूप तय होता है?

भारतीय राजनीति में विपक्ष का कार्य सरकार की नीतियों पर निगरानी रखना है, आलोचना करना है, लेकिन वह आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए, राष्ट्र-विरोधी नहीं। आज हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटाना हो, नागरिकता संशोधन अधिनियम-सीएए, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर-एनआरसी जैसे कानून हों, अग्निपथ योजना हो, या राम मंदिर निर्माण-लगभग हर मुद्दे पर विपक्ष ने एकमत होकर विरोध किया है। चाहे चीन या पाकिस्तान से जुड़ी संवेदनशील मसले हों, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के निर्णय, विपक्ष अक्सर उन बिंदुओं पर एक सुर में सरकार का विरोध करता है, जबकि ऐसे राष्ट्रीयता के मुद्दों पर विपक्ष को सरकार एवं देश के साथ एकजुटता दिखानी चाहिए। यह संयोग नहीं, एक दूषित राजनीतिक रणनीति बनती जा रही है कि जो सरकार करे, उसका विरोध करो, चाहे मुद्दा देशहित का ही क्यों न हो। इन स्थितियों में आम जनता का एक बड़ा सवाल है कि विपक्ष देश के साथ है या सिर्फ सत्ता की भूख के साथ? क्या चुनाव प्रक्रिया पर विरोध करना लोकतंत्र का मजाक नहीं है? क्या न्यायपालिका के निर्णयों को चुनौती देना सिर्फ स्वार्थ की राजनीति नहीं? क्या राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार के साथ खड़े होने से विपक्ष की राजनीति कमजोर हो जाएगी? जब विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करता है, तो उसका नैतिक बल कमजोर होता है, और जनता का विश्वास टूटता है। भारतीय राजनीति को अब रचनात्मक विपक्ष की जरूरत है, ऐसा विपक्ष जो सत्ता में नहीं है, फिर भी राष्ट्र के लिए सत्ता के साथ खड़ा हो सकता है। जो यह समझ सके कि लोकतंत्र सरकार और विपक्ष दोनों से चलता है, लेकिन राष्ट्र सबसे ऊपर है। बिहार में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति इस बात का प्रतीक है कि संस्थाएं अभी भी न्याय और संवैधानिकता की रक्षा कर रही हैं। लेकिन विपक्ष यदि इस निर्णय पर भी नकारात्मक रवैया अपनाता है, तो यह जनता की आकांक्षाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और विकासशील भारत की दिशा के विरुद्ध होगा। विपक्ष को चाहिए कि वह अपनी राजनीति को जनहित से जोड़े, जनविरोध से नहीं। विपक्ष यदि राष्ट्रहित में सोचने की दिशा में खुद को परिवर्तित नहीं करता, तो वह धीरे-धीरे प्रासंगिकता खो देगा।

भारतीय लोकतंत्र की नींव निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी चुनावों पर टिकी होती है। इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने की दिशा में बिहार में चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया मतदाता सूची सुधार अभियान हाल ही में राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना। लेकिन जिस बात ने सबसे अधिक ध्यान खींचा, वह यह है कि इस पूरी कवायद के दौरान विपक्ष एक बार फिर एकजुट होकर इसका विरोध करता नजर आया, भले ही मामला राष्ट्रहित और लोकतंत्र की मजबूती से जुड़ा हो। बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्टों को दुरुस्त करने, फर्जी वोटरों की छंटनी, और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ने का जो कार्य प्रारंभ किया, वह एक सामान्य प्रशासनिक कार्य नहीं था, बल्कि एक लोकतांत्रिक शुद्धिकरण था। यह सुधार न केवल चुनावों को पारदर्शी बनाता है, बल्कि नागरिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। परन्तु कुछ राजनीतिक दलों ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई और इसे जातीय आंकड़ों, राजनीतिक संतुलन और चुनावी गणित से जोड़कर कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण संविधान सम्मत प्रक्रिया है और इसे बाधित नहीं किया जा सकता। अदालत ने चुनाव आयोग की कार्रवाई को न केवल वैध बताया, बल्कि उसे लोकतंत्र के लिए आवश्यक भी बताया। यह फैसला यह भी दर्शाता है कि अब समय आ गया है जब चुनावी ईमानदारी को राजनीतिक शोरगुल और वोट बैंक की राजनीति के शोर में दबाया नहीं जा सकता। विपक्ष की प्रतिक्रिया लगभग स्वचालित होती जा रही है, चाहे मुद्दा हो आर्थिक सुधार का, रक्षा नीति का, विदेश नीति का, या अब मतदाता सूची सुधार का। प्रश्न यह उठता है कि क्या हर सुधार प्रक्रिया, चाहे वह कितनी भी लोकतांत्रिक या पारदर्शी हो, विपक्ष के लिए मात्र एक राजनैतिक खतरा है? विपक्ष का यह रवैया यह दर्शाता है कि उसे संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा कम और अपनी राजनीतिक गणनाओं पर भरोसा अधिक है।

एक सामान्य नागरिक के लिए सबसे बड़ा अधिकार है वोट देना। यदि कोई सुधार प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि एक भी फर्जी वोटर सूची में न हो, कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं, जाति, धर्म या राजनीति से ऊपर उठकर नागरिकता के आधार पर मतदाता सूची बने, तो फिर उसका विरोध क्यों? विपक्ष इस डर से ग्रस्त है कि यदि मतदाता सूची साफ-सुथरी हो गई, तो उनके कथित परंपरागत वोट बैंक कमजोर हो सकते हैं। उन्हें डर है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन यह तर्क लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है। लोकतंत्र जो है, उसे प्रतिबिंबित करे, न कि जो चाहिए, उसे निर्मित करे।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

आतंकवाद में डिजिटल तकनीकों का बढ़ता उपयोग चिन्ताजनक

एफएटीएफ के मुताबिक, 2019 में पुलवामा और 2022 में गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हुए आतंकी हमलों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। पुलवामा में आतंकियों ने आईईडी का इस्तेमाल किया था और इसे बनाने के लिए एल्युमिनियम पाउडर एमेजन से खरीदा गया था। गोरखपुर में हुए हमले में पैसों के लेनदेन में ऑनलाइन जरिया अपनाया गया

-ललित गर्ग

टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की नई रिपोर्ट में आतंकवादी गतिविधियों में डिजिटल तकनीकों के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताई गई है। इस रिपोर्ट ने वैश्विक सुरक्षा के समक्ष एक नई और गहन चुनौती की ओर संकेत करते हुए आतंकवादी गतिविधियों में डिजिटल तकनीकों के बढ़ते प्रयोग को गहन चिन्ताजनक बताया है। रिपोर्ट में ई-कॉमर्स, ऑनलाइन भुगतान, सोशल मीडिया, क्रिप्टोकरेंसी और डार्कनेट जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण और संचालन के बढ़ते खतरे पर न केवल प्रकाश डाला गया है बल्कि गंभीर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट ने आतंकवाद के एक अलग ही पहलू की ओर ध्यान खींचा है। इसमें बताया गया है कि टेक्नोलॉजी तक आतंकी संगठनों की आसान पहुंच उन्हें और खतरनाक बना रही है। इससे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर नई रणनीति एवं नियंत्रण नीति की जरूरत है। विशेष रूप से पाकिस्तान जैसे देशों में पलने-बढ़ने वाले आतंकी संगठन इन तकनीकों का उपयोग कर न केवल फंडिंग जुटा रहे हैं, बल्कि गोपनीयता और पहुँच के नए मार्ग भी तलाश रहे हैं। इसके अलावा, आतंकवादी संगठन अब विकेंद्रीकृत मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं, जैसेकि अल-कायदा क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर धन जुटाना और संचालन करना। भारत ने समय-समय पर पाकिस्तान पोषित एवं पल्लवित आतंकवाद को बेनकाब करते हुए दुनिया से मिल रहे आर्थिक सहयोग पर चिन्ता जताई और कठोर कार्रवाई की मांग की, इस रिपोर्ट को भारत के रुख का समर्थन करने वाले एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।

एफएटीएफ के मुताबिक, 2019 में पुलवामा और 2022 में गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हुए आतंकी हमलों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। पुलवामा में आतंकियों ने आईईडी का इस्तेमाल किया था और इसे बनाने के लिए एल्युमिनियम पाउडर एमेजन से खरीदा गया था। गोरखपुर में हुए हमले में पैसों के लेनदेन में ऑनलाइन जरिया अपनाया गया। गोरखपुर वाले केस में आतंकी विचारधारा से प्रभावित शख्स ने इंटरनैशनल थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन और वीपीएन सर्विस का उपयोग किया था। इस तरह से उसने आईएसआईएल के समर्थन में विदेश में धन भेजा था और उसे भी बाहर से आर्थिक मदद मिली थी। वीपीएन एक डिजिटल तकनीक है जो इंटरनेट उपयोगकर्ता की लोकेशन और पहचान को छुपाती है। जब कोई व्यक्ति वीपीएन का उपयोग करता है, तो उसका इंटरनेट ट्रैफिक एक एन्क्रिप्टेड सुरंग के माध्यम से किसी अन्य देश के सर्वर से होकर गुजरता है। इससे उसकी वास्तविक पहचान छिप जाती है और वह सेंसरशिप, ट्रैकिंग और जियो-रिस्ट्रिक्शन से बच सकता है।

2024 तक दुनिया में 150 करोड़ से अधिक वीपीएन यूजर्स हैं। इनमें से बड़ी संख्या एशिया और मध्य पूर्व से है, जहां सेंसरशिप या निगरानी से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भारत में 12 से 14 करोड़ वीपीएन उपयोगकर्ता हैं। भारत वीपीएन यूजर्स की संख्या में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल है। वीपीएन का उपयोग कर आतंकी सोशल मीडिया और गुप्त चैनलों के जरिए युवाओं को बरगलाने और भर्ती करने का काम करते हैं। कुछ आतंकवादी समूह वीपीएन नेटवर्क का प्रयोग कर सरकारी वेबसाइटों, रक्षा प्रतिष्ठानों और बैंकिंग सिस्टम पर साइबर हमला करते हैं। दुनिया की एक तिहाई आबादी ऑनलाइन शॉपिंग करती है। इस साल ग्लोबल ई-कॉमर्स मार्केट के 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। भारत इस लिस्ट में फिलहाल सातवें नंबर पर है। लेकिन सवाल यह है कि इस डेटा के बीच अगर कुछ संदिग्ध लोग कुछ हजार डॉलर की खरीददारी करते हैं, जिसका इस्तेमाल आगे जाकर किसी आतंकी हमले में होता है, तो उसे चिह्नित कैसे किया जाए? एफएटीएफ ने कुछ दिनों पहले पहलगाम को लेकर कहा था कि इतना बड़ा आतंकी हमला बाहरी आर्थिक मदद के बिना संभव नहीं हो सकता। उसकी हालिया रिपोर्ट इसी बात को और पुष्ट कर देती है। आतंकियों ने अपने काम का तरीका बदल लिया है। वे इंटरनेट की दुनिया की ओट ले रहे हैं, जो ज्यादा खतरनाक है।

एफएटीएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवादी समूहों ने अब पारंपरिक धन स्रोतों के साथ-साथ क्रिप्टोकरेंसी जैसे डिजिटल वित्तीय माध्यमों का भी उपयोग करना शुरू कर दिया है। ये माध्यम उन्हें सरकार की नजरों से बचाते हुए सीमाओं के पार फंडिंग जुटाने की सहूलियत देते हैं। साथ ही, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स, फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स, और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर वे अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं। पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर भले हो गया हो, लेकिन उसके खिलाफ लगे आरोपों में कोई कमी नहीं आई है। अनेक ग्लोबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और एफएटीएफ ऑब्जर्वेशन्स इस बात की पुष्टि करती हैं कि पाकिस्तान में आतंकी गुटों को डिजिटल इकोसिस्टम का खुले तौर पर उपयोग करने दिया जा रहा है, या कभी-कभी सरकार की मौन सहमति से। उदाहरण के रूप में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों ने बिटकॉइन और अन्य डिजिटल टोकन के जरिए फंड जुटाने की नई तरकीबें अपनाई हैं। कई मामलों में आतंकी फंडिंग के लिए फर्जी चैरिटेबल ट्रस्ट और सामाजिक मीडिया अभियानों का सहारा लिया गया है। गजवा-ए-हिंद जैसे डिजिटल प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तानी जमीन से संचालित होकर भारत में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने में लगे हैं।

भारत के विरुद्ध हाइब्रिड वारफेयर और साइबर जिहाद की रणनीति पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों की नीति का हिस्सा बन चुकी है। एफएटीएफ की रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दक्षिण एशिया में भारत सबसे अधिक प्रभावित देश है, जहां डिजिटल माध्यम से न केवल फंडिंग, बल्कि ब्रेनवॉशिंग और भर्ती का कार्य भी तेजी से हो रहा है। जम्मू-कश्मीर में सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को आतंकी संगठनों की ओर आकर्षित किया जाता है। उत्तर पूर्व में उग्रवादी संगठनों को डिजिटल भुगतान और चैनलों के माध्यम से सहायता मिलती रही है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान समेत उन सभी देशों से अपेक्षा की है कि वे डिजिटल वित्तीय निगरानी तंत्र को मजबूत करें। क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर नियमित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें। आतंकी संगठनों के ऑनलाइन अस्तित्व को समाप्त करने के लिए तकनीकी टूल्स विकसित करें। एफएटीएफ का चेतावनी के स्वरों में यह भी कहना है कि यदि आतंक के गढ़ एवं आतंकवाद को पोषित करने वाले इन देशों ने इन सिफारिशों पर अमल नहीं किया तो उन्हें हाई रिस्क जॉन की सूची में डाला जा सकता है। भारत को इस डिजिटल आतंकी खतरे से निपटने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय से एक संयुक्त रणनीति बनानी चाहिए-क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की रियल-टाइम निगरानी, साइबर आतंकवाद पर विशेष फोर्स का गठन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से आतंकी कंटेंट की पहचान और हटाने के लिए मजबूत कानून, डार्क वेब और फेक डोनेशन चैनलों की सतत निगरानी आदि कदम उठाने चाहिए।

डिजिटल तकनीक ने जहां मानव जीवन को सरल और तेज किया है, वहीं इसका दुरुपयोग कर-के आतंकवाद को नया चेहरा देने की कोशिशें चिंता का विषय हैं। एफएटीएफ की चेतावनी को गंभीरता से लेने और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने की जरूरत है। विशेष रूप से पाकिस्तान जैसे देशों पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाना होगा ताकि वे अपनी धरती पर पनप रहे आतंकवाद एवं डिजिटल आतंकवाद के अड्डों को समाप्त करें। तभी एक सुरक्षित डिजिटल विश्व और शांतिपूर्ण वैश्विक समाज की कल्पना की जा सकती है। एफएटीएफ रिपोर्ट विश्लेषण करती है कि आतंकवादियों ने अपने आतंकवादी उद्देश्यों के लिए वैश्विक दर्शकों से धन जुटाने के लिए सोशल मीडिया पर धन उगाहने वाले प्लेटफॉर्म और क्राउडफंडिंग माध्यमों से आतंकवाद के वित्तपोषण प्राप्त किया है। आतंकवादी संगठन पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ डिजिटल तरीकों से भी धन जुटाकर आतंकवाद को अंजाम दे रहे हैं।

भारत ने एफएटीएफ रिपोर्ट को अपने रुख के समर्थन में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जिसमें पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई की मांग की गई है। यह रिपोर्ट आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। यह रिपोर्ट आतंकवाद के वित्तपोषण और संचालन में शामिल देशों और व्यक्तियों पर दबाव बढ़ाने और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने में सहायक हो सकती है।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

खेल/विदेश/कारोबार/फिल्म

भारत के पड़ोसी देश में अचानक घुसे 150 ड्रोन, बरसाने लगे बम, सेना का आया बड़ा बयान

(एजेन्सी)।

भारत के पड़ोसी देश में जबरदस्त एयरस्ट्राइक हुई है। इस एयरस्ट्राइक के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। भयंकर तबाही मची हुई है। ये स्ट्राइक म्यांमार के आतंकवादी संगठन उल्फा आई के ईस्टर्न हेडक्वार्टर पर की गई है। उल्फा आई यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (I) प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन है। ये संगठन भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। लेकिन अचानक इस संगठन पर एयर स्ट्राइक कर दी गई। ये एयर स्ट्राइक किसने की है, वो एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। उल्फा आई ने दावा किया है कि ये एयर स्ट्राइक भारतीय सेना ने की है। अब सवाल है कि क्या भारत ने सही में देश के लिए खतरा बन चुके उल्फा आई के ठिकानों पर ड्रोन से हमला कर दिया। दरअसल, म्यांमार में इस वक्त हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। म्यांमार में कई उग्रवादी संगठन सत्ता में बैठी सेना से लड़ रहे हैं। इनमें से कुछ उग्रवादी संगठन भारत म्यांमर की सीमा के पास भी ऑपरेट करते हैं। ये भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। कई रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में चल रहे इस गृह युद्ध में चीन खुलकर उग्रवादी संगठनों और सत्ता में बैठी सेना दोनों को हथियार दे रहा है। यानी चीन पहले आग लगा रहा है और उसके बाद घी भी डाल रहा है। ऐसे में बिगड़ते हालातों के बीच उल्फा आई ने दावा किया कि 150 ड्रोन अचानक आए और हमारे हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। ये हमला म्यांमार की सीमा के अंदर हुआ है। इस हमले में उल्फा आई के लेफ्टिनेंट जनरल नयन ओसम की मौत हो गई है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन उल्फा (क) ने दावा किया कि भारतीय सेना ने म्यांमार सीमा के पास उनके कैंपों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिनमें समूह के तीन नेताओं की मौत हो गई। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (क) ने एक बयान में कहा कि 13 जुलाई की सुबह उसके कई कैंपों पर ड्रोन से हमला किया गया। हमले में उनके एक टॉप कमांडर की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हुए। उल्फा (क) ने बाद में एक और बयान में कहा कि जब मारे गए नेता का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उसी समय मिसाइलों से फिर से हमला हुआ। हमले में संगठन की 'लोअर काउंसिल' के ब्रिगेडियर गणेश असम और कर्नल प्रदीप असम मारे गए।

भारतीय सेना ने म्यांमार में प्रतिबंधित उग्रवादी समूह यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम-इंडिपेंडेंट (उल्फा-आई) के तीन शीर्ष नेताओं सहित 19 उग्रवादियों के मारे जाने वाले किसी भी अभियान में अपनी संलिप्तता से स्पष्ट रूप से इनकार किया है। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी कर्नल एमएस रावत ने गुवाहाटी में कहा कि भारतीय सेना के पास ऐसे किसी अभियान की कोई जानकारी नहीं है। परेश बरुआ के नेतृत्व वाले प्रतिबंधित उग्रवादी समूह ने दावा किया है कि कल तड़के भारतीय सेना ने म्यांमार स्थित उसके पूर्वी मुख्यालय को ड्रोन से निशाना बनाया।

अंग्रेजों ने की हद पार, ब्रायडन कार्स ने मारी रवींद्र जडेजा को टक्कर

(एजेन्सी)।

भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच का आज आखिरी दिन चल रहा है। इसी बीच रविंद्र जडेजा और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स के बीच मैदान पर टक्कर हो गई। जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि दोंों के बीच बहस हो गई। बाद में इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स को बीच में आकर मामला शांत कराना पड़ा।

इंग्लैंड ने भारत को 193 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत की शुरूआत खराब रही और उसने जल्दी-जल्दी विकेट खो दिए। ये घटना 35वें ओवर की आखिरी गेंद के बाद हुई। जडेजा ने एक शॉट खेला और रन लेने के लिए दौड़े। उसी समय कार्स भी गेंद की तरफ देख रहे थे और दोनों आपस में टकरा गए। कार्स को गुस्सा आ गया क्योंकि उनका संतुलन बिगड़ गया था। जडेजा को भी चोट लग सकती थी। दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद स्टोक्स ने बीच बचाव किया।

वहीं इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जिसमें जडेजा और कार्स के बीच बहस होती दिख रही है। दिन के पहले सेशन में इंग्लैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने भारत के चार बल्लेबाजों को आउट कर दिया। पंत को जोफ्रा आर्चर ने बोल्ड कर दिया और उन्हें गुस्से में मैदान से बाहर जाने का इशारा कर दिया। आर्चर ने पंत को फायरी सेंड ऑफ दिया।

राजकुमार राव अभिनीत मालिक ने पहले वीकेंड पर 15 .02 करोड़ रुपये कमाए

(एजेन्सी)। राजकुमार राव अभिनीत मालिक ने तीन दिनों में देशभर के सिनेमा घरों से कुल 15 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। निमार्ताओं ने सोमवार को यह घोषणा की। कुमार तौरानी की टिप्स फिल्म और जय शेवक्रमणी की नॉर्दर्न लाइट्स फिल्म्स द्वारा निर्मित मालिक का निर्देशन भक्षक फिल्म से प्रसिद्ध हुए पुलकित ने किया है। 1980 के दशक के इलाहाबाद की पृष्ठभूमि पर आधारित यह एक्शन थ्रिलर फिल्म महत्वाकांक्षा, सत्ता और अस्तित्व के संघर्ष की एक मार्मिक कहानी है जो दर्शाती है कि बंदूक, लालच और वफादारी के सहारे चलने वाली दुनिया में तरक्की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। शाहिद, न्यूटन, स्त्री और श्रीकांत जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले राव मालिकमें एक गैंगस्टर का किरदार निभा रहे हैं। निर्माता कंपनी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर फिल्म पोस्टर के साथ एक पोस्ट साझा कर सिनेमा घरों की टिकट खिड़की पर हुई कमाई की जानकारी दी। मालिक ने पहले दिन देशभर में टिकट खिड़की पर 4.02 करोड़ की कमाई के साथ खाता खोला और दूसरे दिन 5.45 करोड़ रुपये कमाए।

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 34% तक बढ़ सकती है, कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग

(एजेन्सी)।

8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद लाखों सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भारी वृद्धि होने वाली है। एम्बिट कैपिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार, वेतन में लगभग 30-34 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। नया वेतनमान जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। हालाँकि, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले, इसे पहले तैयार करना, सरकार को भेजना और फिर मंजूरी देना आवश्यक है।

एक बार मंजूरी मिलने के बाद, 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन, भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभों में बढ़ोतरी होगी। इसका असर लगभग 1.1 करोड़ लोगों पर पड़ेगा, जिनमें लगभग 44 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 68 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं। गौरतलब है कि अभी केवल व्यापक घोषणाएँ ही की गई हैं, जबकि आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा और इसकी शर्तें क्या होंगी, जैसी विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। नए वेतनमान के अनुसार नए वेतन तय करने में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण पहलू है। इससे पहले, 7वें वेतन आयोग में 2.57 के फैक्टर का इस्तेमाल किया

पिछले वेतन आयोगों ने वेतन वृद्धि के विभिन्न स्तरों की सिफारिश की है

जाता था। इसे और विस्तार से समझने के लिए, अगर किसी व्यक्ति का मूल वेतन 7,000 रुपये था, तो संशोधित वेतन आयोग के तहत यह बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह हो गया। 8वें वेतन आयोग के मामले में, यह फैक्टर 1.83 और 2.46 के बीच रहने की संभावना है। एक बार सटीक आंकड़े की पुष्टि हो जाने पर यह कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन वृद्धि की राशि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा।

पिछले वेतन आयोगों ने वेतन वृद्धि के विभिन्न स्तरों की सिफारिश की है। उदाहरण के लिए, जहाँ छठे वेतन आयोग (2006) ने कुल वेतन और भत्तों में लगभग 54 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि का प्रस्ताव रखा था, वहीं सातवें वेतन आयोग (2016) ने मूल वेतन में 14.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि और भत्तों को शामिल करने वाले पहले वर्ष में लगभग 23 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव रखा था।

दीपक राय कान्हा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का शिष्टमंडल जेसीपी से मिला

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर राजेश सिंह से मिलने जाते हुए अधिवक्तागण। (छायाः एसबी)

एसबी संवाददाता

वाराणसी। सोमवार को अधिवक्ता विनोद कुमार पटेल के मामले में अधिवक्ताओं का एक शिष्टमंडल संयुक्त पुलिस आयुक्त राजेश कुमार सिंह से मिला।

संयुक्त पुलिस आयुक्त को दिये गये प्रार्थना पत्र में लोहता थाना के चांदपुर गांव के परमहंस नगर कालोनी निवासी अधिवक्ता विनोद पटेल ने आरोप लगाया कि बारह जुलाई को परमहंस कालोनी में मकान का निर्माण करवा रहा था कॉलोनाइजर अशोक पटेल अपने साथियों के साथ आकर काम रुकवा दिया और ईंट, फरसा आदि हथियार से जानलेवा हमला किया जिससे प्रार्थी और प्रार्थी के परिवार को गम्भीर चोटें आईं तथा मोटरसाइकिल और दुकान क्षतिग्रस्त हो गए। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने लोहता थाना को प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया।

शिष्टमंडल में दीपक राय कान्हा, संजय सिंह दाढ़ी, धीरेन्द्र श्रीवास्तव, बनारस बार के उपाध्यक्ष राघवेन्द्र दूबे, विधु प्रकाश पाण्डेय, अम्बरीष सिंह, सुधा सिंह, गौतम कुमार झा आदि अधिवक्ता शामिल थे।

ट्राई मीडिया जर्नलिस्ट क्लब का कार्यक्रम जिमखाना क्लब में आयोजित

भाजपा जिलाध्यक्ष ने पत्रकार हितों की पैरवी का दिया भरोसा

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजेश कुमार

पंचकूला। ट्राई मीडिया जर्नलिस्ट क्लब द्वारा रविवार को एक महत्वपूर्ण गेट-टुगेदर कार्यक्रम का आयोजन पंचकूला के प्रतिष्ठित जिमखाना क्लब, सेक्टर-3 में किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी पंचकूला के ज़िला अध्यक्ष श्री अजय मित्तल ने शिरकत की। उनके साथ भाजपा जिला उपाध्यक्ष तेजिंदर गुप्ता (टोनी) भी उपस्थित रहे।

क्लब के सदस्यों और पत्रकारों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। फूलों की माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर श्री मित्तल का अभिनंदन किया गया।

यह कार्यक्रम ना केवल क्लब सदस्यों की आपसी मुलाकात और संवाद के लिए एक अहम मंच बना, बल्कि पत्रकारिता से जुड़े मुद्दों और समस्याओं को भी गंभीरता से उठाया गया। पत्रकारों की सुरक्षा, सुविधा और अधिकारों को लेकर चर्चा की गई, वहीं पंचकूला में एक स्थायी प्रेस क्लब की स्थापना की माँग प्रमुखता से उठी।

कार्यक्रम में ट्राई मीडिया जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष ताज मोहम्मद, वरिष्ठ पत्रकार एस के जैन, उपाध्यक्ष श्री सतीश शर्मा, सचिव श्री कमलेश्वर चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव श्री हैप्पी कुमार, कोषाध्यक्ष श्री सुमित कुमार और वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं सहित क्लब के अन्य सक्रिय सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने एक सुर में पत्रकारों के लिए एक समर्पित स्थान-एक प्रेस क्लब-की आवश्यकता को दोहराया, जहाँ न केवल मीडिया प्रतिनिधि मिल-बैठकर अपने विचार साझा कर सकें, बल्कि वह पत्रकारों के लिए सहयोग, सुरक्षा और आत्म-सम्मान का प्रतीक बन सके।

पंचकूला जैसे आधुनिक और तेजी से विकसित हो रहे ज़िले में अब तक एक समर्पित प्रेस क्लब की कमी को लेकर कई पत्रकारों ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एक स्थायी प्रेस क्लब का अभाव पत्रकारों को एकजुट होने और सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पेशेवर गतिविधियों के संचालन में बाधा उत्पन्न करता है। यह प्रेस क्लब ना केवल एक कार्यालय का रूप लेगा, बल्कि संवाद, संवाददाता सम्मेलन, प्रशिक्षण वर्कशॉप और विचार गोष्ठियों के आयोजन का भी केंद्र बन सकता है। अध्यक्ष ताज मोहम्मद ने अपने वक्तव्य में कहा, ट्राई मीडिया जर्नलिस्ट क्लब शुरू से ही पत्रकारों की आवाज को मजबूती देने का काम करता आया है। पंचकूला में प्रेस क्लब की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन और सरकार इस दिशा में सकारात्मक पहल करे।

मुख्य अतिथि अजय मित्तल ने पत्रकारों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और अपनी ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और उनके हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रेस क्लब की स्थापना को लेकर उन्होंने कहा कि इस माँग को वे ज़िला प्रशासन और संबंधित विभागों के समक्ष प्राथमिकता के साथ रखेंगे।

अजय मित्तल ने कहा, पत्रकारों ने हमेशा समाज को जागरूक करने और जनहित के मुद्दों को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में उनका सशक्तिकरण और एकजुटता भी उतनी ही जरूरी है। पंचकूला में प्रेस क्लब का होना आवश्यक है और मैं व्यक्तिगत तौर पर यह बात आगे पहुँचाऊँगा।

कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकारों ने मौजूदा समय में मीडिया कर्मियों को आ रही विभिन्न चुनौतियों पर भी चर्चा की। इनमें फील्ड में काम करते समय सुरक्षा की कमी, सूचना तक पहुंच में अड़चन, प्रशासन से संवाद की सीमितता और पेशेवर सम्मान की कमी जैसी समस्याएँ प्रमुख थीं। सचिव कमलेश्वर चतुर्वेदी ने बताया कि कई बार पत्रकारों को मौके पर कवरेज करते समय अधिकारियों द्वारा उचित सहयोग नहीं दिया जाता। उन्होंने आग्रह किया कि प्रशासन को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएँ ताकि मीडिया प्रतिनिधियों को उनका काम सुचारू रूप से करने दिया जाए।

संयुक्त सचिव हैप्पी कुमार और कोषाध्यक्ष सुमित कुमार ने भी प्रेस की स्वतंत्रता और सुरक्षा को लेकर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि आज मीडिया न केवल खबर देने का माध्यम है, बल्कि समाज की चेतना का दर्पण भी है। ऐसे में पत्रकारों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा जरूरी है। क्लब के अन्य सदस्यों और उपस्थित पत्रकारों ने इस बात पर सहमति जताई कि ऐसे आयोजन नियमित अंतराल पर होने चाहिए ताकि मीडिया से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा हो सके और आपसी समन्वय बना रहे। कार्यक्रम का संचालन कुशलता से किया गया और सभी ने संयम और सौहार्द के साथ अपने विचार साझा किए।

कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार एस के जैन ने सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों और पत्रकारों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि क्लब आने वाले समय में भी पत्रकारों के हितों के लिए कार्य करता रहेगा और प्रेस क्लब की स्थापना को लेकर कदम दर कदम आगे बढ़ाया जाएगा।

यह आयोजन ट्राई मीडिया जर्नलिस्ट क्लब की सक्रियता और पत्रकारों के हितों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्य अतिथि अजय मित्तल द्वारा दिए गए आश्वासन से पत्रकार समुदाय को एक नई उम्मीद मिली है। यदि पंचकूला में प्रेस क्लब की स्थापना हो जाती है, तो यह न केवल मीडिया प्रतिनिधियों के लिए एक उपलब्धि होगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में मीडिया-संवाद और प्रेस की स्वतंत्रता को नया आयाम मिलेगा।

इस मौके पर तारा ठाकुर, संजय पारवाला, अंकित कौशिक, रामेंद्र नाथ शर्मा, चंद्रपाल राणा, अजय सैनी, एसके जैन, कमल कलसी, विपिन लूथरा, ललित, सचिन बराड़, अनिल शर्मा, कुलदीप सैनी, जगदीश चंद्र मल्होत्रा, विशाल मल्होत्रा, सुरेंद्र चौहान, करुणा, कुलदीप सिंह, सोनू सैनी, विजेश कुमार आदि उपस्थित रहे।

जनपद स्तरीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया

एसबी ब्यूरो प्रमुख इंतजार हुसैन

बदायूं। चंद्रिका देवी इंटर कॉलेज उझानी रोड बदायूं में मिशन निदेशक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डी0डी0यू0-जी0के0वाई0) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना के तत्वाधान में जनपद स्तरीय वृहद रोजगार मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता द्वारा फीता काट कर किया गया। रोजगार मेले में 14 नियोक्ता/कम्पनी के प्रतिनिधियों द्वारा नियोजक के रूप में प्रतिभाग किया गया। उक्त रोजगार मेला में कुल 437 अभ्यार्थियों द्वारा प्रतिभाग कर साक्षात्कार मे भाग लिया गया, जिनमें से 113 अभ्यार्थियों का चयन विभिन्न कम्पनियों के द्वारा किया गया। चयनित अभ्यार्थियों को जनप्रतिनिधियों/माननीयों के द्वारा मंच से ही नियुक्ति पत्र दिनांक 15-07-2025 को विश्व युवा कौशल दिवस के उपलक्ष में प्रदान किया जाएगा।

उक्त कार्यक्रम में जिला समन्वयक सुरेंद्र कुमार वार्ष्णेय, जिला कौशल प्रबंधन मो० एहतिशाम, कार्यालय सहायक नीरज कुमार एवं जिला रोजगार सहायता कार्यालय से संजय कुमार उपस्थित रहे।

पंजाब विधानसभा द्वारा पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स (संशोधन) बिल, 2025 और पंजाब विनियोग अधिनियम (रपील) बिल, 2025 सर्वसम्मति से पारित

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा ने राज्य के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा द्वारा प्रस्तुत पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स (संशोधन) बिल, 2025 और पंजाब विनियोग अधिनियम (रपील) बिल, 2025 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। पंजाब राज्य विकास टैक्स (संशोधन) बिल, 2025 का उद्देश्य पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स एक्ट, 2018 को सुचारू बनाना और इसकी दक्षता को बढ़ाना है, जिसके तहत प्रत्येक आयकरदाता द्वारा 200 रुपये प्रति माह कर अदा किया जाता है, जिससे वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 190.36 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त हुआ।

वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के प्रतिनिधियों ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा पारित मौजूदा एक्ट में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों के बारे में उनसे संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ विचार-विमर्श के बाद संशोधित बिल में टैक्स ढांचे के विभिन्न पहलुओं को सरल बनाने और स्पष्ट करने के लिए कई मुख्य प्रावधान तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि करदाताओं के लिए एक एकमुश्त टैक्स भुगतान विकल्प जैसी महत्वपूर्ण सुविधा दी गई है, जिससे किसी भी व्यक्ति को मासिक 200 रुपये (वार्षिक 2400 रुपये) के बजाय एक बार में 2200 रुपये जमा करने की सुविधा होगी, जिससे इस कर के भुगतान की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

इसके अतिरिक्त, एक बार के निपटारे की विधि को सुविधाजनक बनाने के लिए पीएसडीटी एक्ट में एक नई धारा 11ए जोड़ी गई है। विशेष परिस्थितियों से उत्पन्न जटिलताओं को हल करने के लिए, बिल में पीएसडीटी एक्ट के अंतर्गत नई धाराओं 11बी, 11सी और 11डी को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये धाराएं किसी पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु, कंपनियों के परिसमापन या कॉर्पोरेट दिवालियापन के मामलों से जुड़े मामलों में टैक्स भुगतान देनदारियों को दशाएंगी।

इसके अलावा, अनावश्यक उलझनों को दूर करने के लिए बिल में दोहरी देनदारी की स्थितियों में केवल एक ही पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। बिल व्यक्तिगत और एकमात्र स्वामित्व दोनों रूपों में अलग-अलग पंजीकरणों की आवश्यकता को प्रभावी ढंग से समाप्त करता है। अंततः, एक महत्वपूर्ण संशोधन पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स एक्ट, 2018 के अधीन देय अधिकतम जुर्माने को सीमित करने का है, जिसके तहत जुर्मानें की राशि संबंधित टैक्स बकाया से अधिक नहीं होगी।

पंजाब विनियोग अधिनियम (रपील) बिल, 2025 पिछले कई वर्षों के दौरान राज्य की विधायी संरचना के तहत कई पुराने और समाप्ति अवधि पूरी कर चुके एप्रोप्रिएशन एक्ट्स (मनी बिल्स) को रद्द करने के लिए लाया गया है।

भा.कि.यू. (अराजनैतिक) ने चार सूत्रीय मांगों को लेकर उपजिलाधिकारी बारा को सौंपा ज्ञापन

संजना भारती संवाददाता

मनोज कुमार बिन्द

बारा। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) की किसान मजदूर पंचायत यमुनापार अध्यक्ष दीपक तिवारी की अगुआई में बारा तहसील में लगाई गई जिसमें चार सूत्रीय मांगों को लेकर उपजिलाधिकारी बारा को सौंपा गया ज्ञापन जो निम्लिखित हैं।

ppgcl बारा पावर प्लांट में क्लासिक सिग्नल में काम कर रहे मजदूरों के साथ ठेकेदार मनोज सिंह द्वारा बंधुआ मजदूरी जैसे व्यवहार किया जा रहा है मनोज सिंह के ऊपर तत्काल कार्यवाही हो।

अल्ट्राटेक सीमेंट कम्पनी को पूर्व में नोटिस के जरिए अवगत कराया जा चुका है कि हाइवे के किनारे गाड़ियों को न खड़ा किया जाए जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हरों और उमापुर टोल पर ओवरलोड बंद हो और निकाले गए लोकल के वर्करों को वापस रखा जाए। ओशा सोनवर्षा में 60 वर्षों से खुला हॉस्पिटल स्थानांतरित न किया जाए उसे स्थाई रखा जाए। इन सभी मांगो को लेकर उपजिलाधिकारी बारा को ज्ञापन सौंपा गया और अवगत कराया गया कि अगर इन मुद्दों पर कठोर कार्रवाई न हुई तो 25 जुलाई को कमिश्नरी परिषद में किसान महापंचायत पर जवाब देना होगा इस किसान पंचायत में प्रदेश और मंडल के कई पदाधिकारी मौजूद रहे जिसमे प्रदेश सचिव लाल पुष्पराज सिंह, मंडल अध्यक्ष बबलू दुबे, जिलाध्यक्ष सनी शुक्ला, महासचिव अंकुश शुक्ला, तहसील अध्यक्ष आशीष शुक्ला शंकरगढ़ ब्लाक अध्यक्ष पंकज कुशवाहा सहित सैकड़ों की संख्या में संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में शिवभक्तों की उमड़ी भीड़

संजना भारती संवाददाता

भरगामा (अररिया)। सावन के पहले सोमवार को भरगामा प्रखंड क्षेत्र के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में अहले सुबह से हीं शिवभक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना दिया। पुलिस-प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए थे। जगह-जगह पुलिस बल तैनात किया गया था। बता दें कि श्रवेश्वरनाथ शिव मंदिर जयनगर,महादेव मंदिर रघुनाथपुर, भरगामा, शंकरपुर शिव मंदिर समेत सभी प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने शिव का अभिषेक किया।

भक्तों ने गंगाजल, दूध, दही, शहद से भगवान का अभिषेक किया। साथ हीं बेलपत्र, भांग और धतूरा भी अर्पित

किया। पंडितों के अनुसार सावन माह में रूद्राभिषेक का विशेष महत्व है। इस दौरान किए गए रूद्राभिषेक से परिवार में सुख-समृद्धि आती है।

इसी कारण पंडितों के पास पूरे सावन माह के लिए रूद्राभिषेक की एडवांस बुकिंग चल रही है। बता दें कि सभी सुहागिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर शिवलिंग का जलाभिषेक किया।

मंदिरों में घंटा-घड़ियाल की आवाज गूंजती रही। भक्तों का मानना है कि सावन में शिव मंत्रों का जाप और रूद्राभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं।

रिमझिम बारिश के बीच निकली कावड़ और कलश यात्रा

संजना भारती संवाददाता

टोंक। भारतीय सनातन मडंल की ओर से द्वितीय विशाल कावड़ व कलश यात्रा रविवार को रिमझिम बारिश कर बीच निकली। कांवड यात्रा में टोंक शहर के रहने वाले मशहूर सिंगर धनराज साहू का दो साल का पोता राघव साहू से लेकर किशोर और किशोरिया, महिला-पुरुष, युवक-युवतियां आदि शामिल हुई। इसमें लोग भगवान के जयकारे लगाते चल रहे थे। वहीं सिर पर कलश लेकर चल रही कई युवतियों में गंगा का भाव (प्रेत आत्मा) भी आया। लोग उनके सामने नारियल फोड़कर और हाथ जोड़ धोक लगाकर मनाते नजर आये।

भारतीय सनातन मंडल के सदस्यों ने बताया कि पिछली साल की तरह इस बार भी सनातन एकता के रंग में रंगी भगवा टोली, हर-हर महादेव के जयघोष के साथ आज सुबह कावड़ लेकर निकली।

इसमें करीब आठ सौ कावंडिये शामिल हुए। इसमें महिलाये भी बड़ी संख्या में कलश लेकर चल रहे थे। हेमंत पंवार ने बताया कि कावंड व कलश यात्रा छावनी के श्रीराधा-कृष्ण मंदिर से विधिवत कलश पूजन के साथ शुरू हुई। यह पुलिस लाइन, बमोर गेट, गांधी पार्क, घंटाघर, हुए मुख्य बाजार से होकर, बड़ा कुआ, सवाई माधोपुर चौराहा होते हुए मंशापूर्ण भूतेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। जहां कावंड में लाए जल से कांवडियों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया।

युवा केवल भविष्य की आशा नहीं, बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति हैं: अतीकुर रहमान

संजना भारती संवाददाता

मोतिहारी। मोतिहारी राजेन्द्र भवन (टाउन हॉल) में बीते रविवार को हिंदुस्तान आवाम वॉइस एंड ऑर्गनाइजेशन (हावो) द्वारा आयोजित चम्पारण यूथ चौपाल में सैकड़ों युवाओं ने जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि विचारों, चिंतन और युवा नेतृत्व की ऊर्जा से भरा एक सामाजिक आंदोलन बनकर उभरा।

कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा नेतृत्व, सामाजिक बदलाव और बाढ़ संकट जैसे ज्वलंत मुद्दों पर गहन विमर्श हुआ। विचारों के इस आदान-प्रदान ने नई दिशा, दृष्टिकोण और संभावनाओं के द्वार खोले। इस प्रेरणादायक पहल का मुख्य उद्देश्य था-युवाओं के बीच सार्थक संवाद को प्रोत्साहित करना, उनके विचारों को सकारात्मक दिशा देना, और उन्हें भावी नेतृत्व के लिए सक्षम बनाना।

कार्यक्रम की शुरूआत दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगान के साथ हुई। इसके पश्चात हावो के संस्थापक अतीकुर रहमान ने संगठन की मूल विचारधारा और 'चौपाल' के उद्देश्यों को विस्तार से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, "युवा केवल भविष्य की आशा नहीं, बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति हैं। यदि यह शक्ति संगठित और जागरूक हो जाए, तो समाज में परिवर्तन अवश्यंभावी है। एक दिशा प्राप्त युवा चेतना समाज की नियति तक बदल सकती है।"

मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित आईजी विकास वैभव ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा, "चम्पारण का भविष्य केवल राजनीति से नहीं, बल्कि शिक्षा, समता और उद्यमिता की शक्ति से संवर सकता है। युवाओं को जॉब-सीकर नहीं, जॉब-क्रिएटर बनना होगा-यही सामाजिक क्रांति की शुरूआत है।" स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे रहमानिया मेडिकल सेंटर के चेयरमैन डॉ. तबरेज अजीज ने युवाओं को चिकित्सा और जनसेवा के क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा सांसद आनंद मोहन, विधायक डॉ. शमीम अहमद (नरकटिया), महापौर प्रीति गुप्ता (मोतिहारी), जिप सदस्य ई. तौसिफुर रहमान, राणा रंजीत, अब्बास अली (चेयरपर्सन, डॉन पब्लिक स्कूल), वरिष्ठ पत्रकार ओजैर अंजुम तथा कुमार अमित जैसे विशिष्ट जन उपस्थित रहे और अपने विचार साझा किए। पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण से आए दर्जनों छात्र-छात्राओं ने यूथ स्पीकर के रूप में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। हावो द्वारा सभी युवा वक्ताओं को प्रमाण-पत्र और स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही, बीते सात वर्षों से संगठन में सक्रिय और समर्पित योगदान देने वाले युवाओं को हावो लीडर्स अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर हावो के अध्यक्ष सौफुर्रहमान, उपाध्यक्ष शाहिद इकबाल, मुख्य वक्ता राज कुमार मिश्रा, नुमान जिया, मजीद अली, शाहिद अनवर, समद अदिल, चैतन्य श्रीवास्तव, प्रिंस कुमार, पूजा वर्मा, वैष्णवी कुमारी सहित चम्पारण के विभिन्न अनुमंडलों व प्रखंडों से आए सैकड़ों युवा तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

जनता दर्शन में विधायक ने सुनी लोगों की समस्याएं

■ मौके पर दिए समाधान के निर्देश, बोले-जनसेवा है सर्वोपरि

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। विधायक जगमोहन आनंद ने सोमवार को भाजपा कार्यालय कर्ण कमल में जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत आमजन की समस्याएं सुनीं। बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष को संबंधित विभागों को भेजते हुए शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

विधायक आनंद ने कहा कि जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वह जनता की आवाज सुने और समय पर समस्याओं का हल करवाए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि आमजन की शिकायतों को गंभीरता से लें और टालमटोल की प्रवृत्ति से बचें।

जगमोहन आनंद ने कहा कि करनाल विधानसभा क्षेत्र का कोई भी निवासी उनसे सीधे मिल सकता है। कैंप कार्यालय में शिकायत दर्ज करने के लिए कर्मचारी प्रतिदिन उपस्थित रहता है, और हर शिकायत का फॉलोअप नियमित रूप से किया जाता है। जनता दर्शन के बाद विधायक ने भाजपा की नवगठित कार्यकारिणी के सदस्यों और मनोनीत पार्षदों से मुलाकात की। इस दौरान शहर की प्रमुख समस्याओं, संगठन के विस्तार और आगामी कार्ययोजनाओं पर विस्तार से बातचीत हुई।

विधायक ने सभी पार्षदों को कर्मठता और निष्ठा से काम करने की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार "हरियाणा एक, हरियाणवी एक" के मंत्र पर बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कर रही है।

केंद्र सरकार की रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना से युवाओं को मिलेगा बड़ा लाभ : राव नरबीर सिंह

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम का स्वागत करते हुए कहा कि यह योजना राज्य के एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों में रोजगार पाने वाले नए कर्मचारियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। राव नरबीर सिंह आज केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया द्वारा राज्यों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग ले रहे थे। वे हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ से इस वर्चुअल बैठक में जुड़े।

उन्होंने बताया कि 1 जुलाई, 2025 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इस योजना को मंजूरी दी गई है। योजना का उद्देश्य रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रत्यक्ष लाभ देना है। इसके लिए प्रारंभिक चरण में 99,446 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और आने वाले दो वर्षों में देशभर में 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना आगामी 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 तक प्रभावी रहेगी। पहली बार रोजगार में आने वाले 15 हजार रुपये तक मासिक वेतन वाले कर्मचारियों को दो किस्तों में सरकार की ओर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बशर्ते कि कर्मचारी कम से कम छह महीने नियोक्ता के पास रोल पर रहे। इसी प्रकार नियोक्ता को दस हजार रुपये तक की सैलरी पर एक हजार रुपये मासिक, दस हजार रुपये से अधिक व बीस हजार रुपये तक दो हजार रुपये मासिक तथा बीस हजार रुपये से अधिक व एक लाख रुपये तक की सैलरी पर तीन हजार रुपये तक मासिक सहायता दी जाएगी। इस अवसर पर श्रम आयुक्त डॉ. मनीराम शर्मा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक श्री डी. के. बेहरा तथा रोजगार, श्रम एवं उद्योग विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

'कॉलेज बनाओ-सिवरेज हटाओ' संघर्ष समिति की तपस्या रंग लाई

■ मुख्यमंत्री हरियाणा ने राजौद में सरकारी कॉलेज निर्माण में नियमों में संशोधन के दिए निर्देश

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

राजौंद। मुख्यमंत्री हरियाणा ने कैथल में आयोजित कार्यक्रम में गत शनिवार जिला कैथल के लिए विभिन्न कल्याणकारी, विकासात्मक, जनहितैषी कार्यों की घोषणा की थी। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री हरियाणा ने राजौद में बनने वाले सरकारी कॉलेज के विषय में कहा कि राजौंद में सरकारी कॉलेज के भवन को पांच एकड़ भूमि में ही बहु मंजिला बनाए जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं- कहा गया कि इसके लिए सरकार ने नियमों में विशेष छूट दी गई है।

संघर्ष समिति प्रवक्ता समाजसेवी सतविंदर राणा उर्फ काका राणा ने दैनिक संजना भारती पत्रकार से फोन पर बात करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी का राजौंद में संघर्ष समिति की मांग के अनुसार सरकारी बस अड्डे के सामने पीडब्ल्यूडी परिसर में 5 एकड़ में सरकारी कॉलेज बनाने के दिशा निर्देश अधिकारियों को देखकर संघर्ष समिति की पुरानी मांग को पूरा किया है। इसके लिए संघर्ष समिति मुख्यमंत्री हरियाणा का बार-बार धन्यवाद करती है। उन्होंने बताया कि संघर्ष समिति अपनी इस मांग को लेकर राजौंद में धरना स्थल पर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक संगठनों, समाजसेवियों के साथ लंबे समय तक तपस्या करती रही। उन्हें भाजपा के विभिन्न नेताओं, पदाधिकारियों सहित, विशेष रूप से सांसद कुरुक्षेत्र नवीन जिंदल ने आश्वासन दिया था कि संघर्ष समिति की मांग के अनुसार राजौंद का सरकारी कॉलेज बस अड्डे के सामने, पीडब्ल्यूडी परिसर में ही बनाया जाएगा और अब मुख्यमंत्री हरियाणा ने संघर्ष समिति की उक्त मांग को स्वीकार करते हुए नियमों में फेर बदल कर 5 एकड़ जमीन में ही बहुमंजिला सरकारी कॉलेज बनाने की घोषणा कर राजौंद के लोगों, क्षेत्र के लोगों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब राजौंद के नागरिक व संघर्ष समिति मुख्यमंत्री हरियाणा, सांसद नवीन जिंदल, कैबिनेट, बीजेपी हरियाणा प्रभारी, जिला प्रभारी, राजौंद मीडिया सहित हर उस नेता का धन्यवाद करती है जिसने संघर्ष समिति की इस मांग को पूरा करने में यथायोग्य सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि राजौंद में बहुत जल्द राजौंद में संघर्ष समिति द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित कर सहयोग करने वाले सभी साथियों का संघर्ष समिति प्रधान राकेश राणा व सभी पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी।

सांसद कुरूक्षेत्र नवीन जिंदल।

पूर्व सैनिकों की समस्याओं को लेकर समस्त भारतीय पूर्व सैनिक सभा की बैठक आयोजित

■ ईसीएचएस, सीएसडी और पैनल अस्पतालों की व्यवस्थाओं में सुधार की उठी मांग

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। करनाल में समस्त भारतीय पूर्व सैनिक सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कृष्णा फौजी बड़ोता ने की। बैठक का उद्देश्य वीर नारियों व पूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुनना और उनके समाधान के लिए रणनीति तैयार करना रहा।

बैठक में ईसीएचएस, सीएसडी कैंटीन, सैनिक बोर्ड और पैनल अस्पतालों से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। डॉ. बड़ोता ने कहा कि कई पैनल अस्पतालों में पूर्व सैनिकों को इलाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह सीएसडी कैंटीन से जुड़ी तकनीकी समस्याएं और सैनिक बोर्ड की फाइलों में देरी भी बड़ी चिंता का विषय है।

बैठक में कैप्टन सतबीर, सूबेदार रामस्वरूप, सूबेदार अनूप मान, दयानंद अहलावत, सुभाष बड़ोता, मनोज सलवान सहित दर्जनों पूर्व सैनिक मौजूद रहे। सभी ने अनुभव साझा किए और एक मंच से आवाज उठाने की जरूरत बताई।

डॉ. बड़ोता ने आश्वासन दिया कि इन समस्याओं को संबंधित अधिकारियों के समक्ष जल्द रखा जाएगा। सभा के अंत में सभी पूर्व सैनिकों ने एक स्वर में पूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। यह बैठक एकजुटता और अधिकारों की रक्षा की दिशा में अहम कदम साबित हुई।

बुलंदी से दायित्व का निर्वहन करें महिला जनप्रतिनिधि : निर्मल बैरागी

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम की अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेत्री निर्मल बैरागी ने महिला जनप्रतिनिधियों का आवाहन किया है कि वे आगे बढकर बुलंदी के साथ जनता द्वारा उन्हें सौंपे गए दायित्व का निर्वहन करें। बैरागी हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित एक विचार गोष्ठी में महिला जनप्रतिनिधियों के सम्मुख आने वाली चुनौतियों और उनसे निपटने के तौर तरीकों पर अपने अनुभव साझा कर रही थीं। गोष्ठी की अध्यक्षता हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के निदेशक डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान ने की। इससे पहले उन्होंने संस्थान परिसर पहुंचकर नवनियुक्त निदेशक डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान को शुभकामनाएं दीं।

निगम अध्यक्ष निर्मल बैरागी ने कहा कि उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन 90 के दशक में सरपंच के रूप में शुरू किया और नया पंचायती राज अधिनियम के लागू होने के बाद वे अपने गांव की पहली महिला सरपंच बनीं। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए नेक नीयत और कर्तव्यनिष्ठा का भाव काफी होता है। उन्होंने पंचायतों में महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की सराहना की। इस अवसर पर डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान ने चेयरपर्सन निर्मल बैरागी की कार्यशैली को महिला सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए अनुकरणीय बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान प्रदेश में कुशल और प्रभावी महिला नेतृत्व के विकास में कारगर भूमिका निभाने के लिए व्यापक कार्य योजना का निर्माण कर उसे क्रियान्वित करेगा। भाजपा के नवनियुक्त जिला प्रवक्ता शिवनाथ कपूर ने भी इस अवसर पर डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार जताया। कार्यक्रम के बाद प्रतिभागियों ने निर्मला बैरागी और डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान की अगुवाई मे बेल-पत्र का पौधा लगा कर श्रावण मास के प्रथम सोमवार को भगवान भोलेनाथ को नमन किया।

इस अवसर पर शिवनाथ कपूर, नवीन कपूर, राजपाल हैबतपुर (भाजपा मंडल अध्यक्ष निगदू), जोनी राणा (भाजपा मंडल अध्यक्ष गुनियाना), सोहन लाल जांगड़ा, ईश चोपड़ा, सुनीता सिंह, सर्जन सिंह, संजीव चौहान (सदस्य भगत सिंह विद्यार्थी परिषद), डॉक्टर भगत सिंह, सरदार जसविंदर सिंह (सरपंच प्रतिनिधि ठरवा माजरा), सरदार बलजीत सिंह, सरदार जोगा सिंह गोराया डाचर उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेले में उमड़ा युवाओं का सैलाब

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। बाबू मूलचंद जैन राजकीय आईटीआई में सोमवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एडीसी सोनू भट्ट ने मुख्य अतिथि के तौर पर किया। संस्थान के प्रधानाचार्य राकेश भाटिया ने उन्हें आईटीआई की गतिविधियों, उपलब्धियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी।

मुख्य अतिथि सोनू भट्ट ने कहा कि अप्रेंटिसशिप युवाओं के भविष्य को संवारने का एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु और उद्योग एक-दूसरे के पूरक हैं और ऐसे मेलों से दोनों को लाभ होता है। उन्होंने विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए

■ 20 से अधिक बड़ी कंपनियों ने किया प्रतिभाग, 1000 से ज्यादा युवाओं ने कराया पंजीकरण

अप्रेंटिसशिप के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानाचार्य राकेश भाटिया ने बताया कि मेले में एक हजार से अधिक अंतिम वर्ष के छात्रों और पासआउट्स ने भाग लिया। पंजाब, हरियाणा और एनसीआर की 20 से अधिक प्रमुख मल्टीनेशनल कंपनियों ने इसमें हिस्सा लेकर छात्रों को रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए। उन्होंने कहा कि यह मेला न केवल युवाओं को रोजगार से जोड़ने वाला मंच रहा, बल्कि इससे छात्रों का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। यह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप योजना के तहत युवाओं के कौशल विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह आयोजन छात्रों के लिए न सिर्फ एक सुनहरा मौका रहा, बल्कि उन्हें सीधे कंपनियों से संवाद करने का अवसर भी मिला, जो उनके करियर को नई दिशा देने में सहायक होगा।

मुख्य बिंदुः

1000+ युवाओं ने कराया पंजीकरण। पंजाब, हरियाणा व एनसीआर की 20+ कंपनियों ने की भागीदारी। उद्योग और प्रशिक्षु को जोड़ने का बना प्रभावी सेतु। छात्रों को रोजगार और प्रशिक्षण दोनों के अवसर मिले।

राजौंद में दादा खेड़ा तालाब से अवैध कब्जा हटाने पहुंचा प्रशासनिक अमला

मंगलवार सुबह 10:00 तक दुकान खाली करने का कब्जाधारी दुकानदारों को दिया अल्टीमेटम

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

राजौंद। राजौंद में दादा खेड़ा के पास मेन रोड पर बनी छः दुकानों को नपा प्रशासन ने अवैध करार दिया हुआ है। नपा प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि यह छह दुकान दादा खेड़ा के तालाब पर अवैध कब्जा करके बनाई गई है।

अवैध कब्जा हटाने ड्यूटी मैजिस्ट्रेट एसडीओ बिजली विभाग राजौंद योगेश कुमार के नेतृत्व में पहुंची नगर पालिका प्रशासन राजौंद व पुलिस प्रशासन राजौंद की टीम दोपहर बाद मौके पर पहुंची व दुकानदारों को तुरंत दुकान खाली करने का निर्देश दिया जिसका दुकानदार पालन करते हुए नजर आए।दुकानदारों ने आनन-फानन में वाहन मंगवाकर अपनी दुकानों का माल वाहनों में लोड करना शुरू कर दिया। नपा सचिव नरेंद्र शर्मा ने बताया कि कब्जाधारी दुकानदारों ने राजौद में नगर पालिका बनने से पूर्व पंचायती राज के समय दादा खेड़ा के तालाब को मिट्टी से भरकर उसके ऊपर नाजायज दुकानें बनाई हुई है। बताया गया कि कुछ कब्जाधारियों ने दुकानें बनाकर आगे किराए पर दे रखी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश व सरकार व प्रशासन के आदेश अनुसार राजौद नगर में सभी सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कब्जाधारियों को तीन बार नोटिस दिए जा चुके हैं। इन कब्जाधारियों को नगर पालिका कार्यालय राजौद में बुलाकर समझाया जा चुका है। उसके बाद भी कब्जाधारी दुकान खाली नहीं कर रहे थे। इसलिए आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट योगेश कुमार की अगुवाई में नपा प्रशासन राजौंद, राजौंद पुलिस बल व पीला पंजा लेकर दुकानों से नाजायज कब्जा हटवाने के लिए पहुंचे।

नपा भवन निरीक्षक अशोक कुमार, जेई अश्वनी कुमार, सफाई निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि तीन बार लिखित नोटिस दिया जा चुका है। कई बार नगर पालिका कार्यालय में बुलाकर हिदायत दी जा चुकी थी। उसके बाद भी दुकान खाली नहीं की गई। सोमवार, नगर पालिका प्रशासन ड्यूटी मजिस्ट्रेट योगेश कुमार के निर्देशन में कब्जा हटवाने पहुंचा है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीओ बिजली विभाग राजौंद योगेश कुमार ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार किसी भी तालाब की शेप या नेचर चेंज नहीं की जा सकती। यह दुकान दादा खेड़ा तालाब की भूमि पर बनाई गई है। इसलिए इनको हटाया जा रहा है। इस दौरान दुकानदार लगातार अपनी दुकानों का माल, छप्पर, शटर उतार कर ट्रैक्टर ट्राली, फोर व्हीलर में लोड करते रहे। बताया गया कि दुकानदारों ने राजौंद प्रशासन से अनुरोध किया कि उन्हें दुकान खाली करने के लिए कल मंगलवार सुबह 10:00 बजे तक का समय दिया जाए। ताकि वे अपना माल निकाल कर सुरक्षित अन्य स्थान पर रख ले। जिसे प्रशासन ने स्वीकार कर लिया। नगर पालिका सचिव ने बताया कि दुकानदारों के अनुरोध पर कल 15 जुलाई, मंगलवार, सुबह 10:00 बजे का तक दुकान खाली करने का समय दिया गया है। कल सुबह दस बजे प्रशासनिक अमला कार्रवाई करने के लिए फिर मौके पर फिर पहुंचेगा। नपा सचिव ने संबंधित दुकानदारों से अनुरोध किया गया है कि वे दुकान खाली कर दें। दुकान खाली नहीं की गई तो उसका जिम्मेदार खुद दुकानदार होंगे।

बताया गया कि दुकानदारों ने मंगलवार, 15 जूलाई सुबह दुकान खाली करने का आश्वासन दिया है।

■ ड्यूटी मजिस्ट्रेट योगेश कुमार, नपा सचिव नरेंद्र शर्मा, भवन निरीक्षक अशोक कुमार, जेई अश्विनी कुमार, पुलिस थाना राजौद की टीम पहुंची मौके पर

हाफ मैराथन के सफल आयोजन पर डीसी ने दी जिलावासियों को बधाई व जताया आभार

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। रविवार को कैथल में आयोजित हाफ मैराथन के आयोजन को सफल बनाने के लिए डीसी प्रीति ने सभी जिलासियों, स्कूल-कॉलेज के बच्चों सहित कर्मचारियों व अधिकारियों को बधाई देते हुए सभी का आभार व्यक्त किया है। डीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कैथल में हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इससे पूर्व एक दिन पहले विभिन्न बैठकों का आयोजन कर जन प्रतिनिधियों व आमजन की सुनवाई की। साथ ही अधिकारियों को बैठक लेकर विकास कार्यों, सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। हाफ मैराथन में पूरे जिले से हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। सभी की सामूहिक भागीदारी से यह आयोजन सफल हो पाया। इस मैराथन में युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। उमस भरी गर्मी के बावजूद हजारों धावकों ने पांच, दस और 21 किलोमीटर की दौड़ पूरे जोश के साथ संपन्न की।

डीसी प्रीति ने कहा कि मैराथन के दौरान हरियाणा को नशा मुक्त बनाने का जो संकल्प लिया है, उसे बखूबी निभाएं। सभी प्रतिभागी स्वयं भी नशे से दूर रहें और अपने परिवार, आसपास के लोगों को नशा न करने के प्रति जागरूक करें, ताकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ड्रग फ्री

■ कहा-मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन अनुसार जल्द पूरे होंगे जिले में लंबित कार्य, अधिकारियों को जारी किए निर्देश

हरियाणा के सपने को साकार किया जा सके। उन्होंने मैराथन को सफल बनाने के लिए सभी जिला वासियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, समाजसेवी संस्थाओं, विद्यार्थियों, स्वयंसेवक, एनसीसी कैडेट्स व जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद व्यक्त किया। डीसी ने कहा कि अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जल्द से जल्द लंबित कार्यों को पूरा करें। आम लोगों की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई कर उन्हें राहत पहुंचाएं। मैराथन कार्यक्रम में सूचना, जन संपर्क विभाग की टीम ने मुख्यमंत्री नायब सिंह द्वारा करवाए गए विकास कार्यों एवं उनकी नीतियों पर आधारित रागिनी गाकर सभी का मन मोह लिया। मुख्यमंत्री व आमजन को रागिनी खूब पसंद आई। यही नहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कलाकारों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। यह रागनी डीआईपीआरओ नसीब सैनी के मार्गदर्शन में तैयार की गई थी। कलाकारों की टीम में डीआई रामफल शर्मा, जयपाल, जगदीश, रवि, मनोज कुमार, मदन, प्रदीप शामिल रहे।